

केवल मैं अपनी
जीवन अच्छा
कर सकता हूँ। कोई
भी मेरे लिए ऐसा नहीं
कर सकता।
- अज्ञात



सनी हिन्दुस्तानी छुपी हुई प्रतिभा

और अपनी कमजोर पृष्ठभूमि के बावजूद यह करिश्मा कर दिखाने वाले सनी हिन्दुस्तानी कोई पहले इंसान नहीं हैं। इसी शो का पिछला सीजन जीतने वाले मेवात के सलमान अली के घर का हाल भी कमोबेश ऐसा ही था।

अमर यादव।

देश के सबसे चर्चित सिंगिंग-बेस्ड टीवी रियलिटी शो के हालिया सीजन के विजेता सनी हिन्दुस्तानी पंजाब के बेहद गरीब, मेहनतकश परिवार से आते हैं। बठिंडा के सनी इंडियन आइडल में भाग लेने से पहले तक बूट पॉलिश किया करते थे। उनके दिवंगत पिता भी यही काम करते थे, जबकि मां घूम-घूम कर गुब्बारे बेचती रही हैं। कई बार उनके सामने दूसरे घरों से मांगकर खाना पकाने की नौबत आ जाती थी। और अपनी कमजोर पृष्ठभूमि के बावजूद यह करिश्मा कर दिखाने वाले सनी हिन्दुस्तानी कोई पहले इंसान नहीं हैं। इसी शो का पिछला सीजन जीतने वाले मेवात के सलमान अली के घर का हाल भी कमोबेश ऐसा ही था। जब भी सलमान का कार्यक्रम आता, उसे देखने के लिए उनके परिवार के लोग पड़ोसियों के घर

चले जाते थे, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था। इतने कमजोर तबकों के नौजवानों का गीत-संगीत की दुनिया में इस तरह छा जाने को एक नई परिघटना के रूप में देखा जा रहा है। सिलेब्रिटीज के दायरे में कमजोर लोगों के लिए स्पेस बनना इसका एक पहलू है। ज्यादा बड़ी बात यह कि साधारण से साधारण व्यक्ति में भी भागीदारी का भाव पैदा हुआ है। सिस्टम में उसे अपने लिए थोड़ी गुंजाइश दिखने लगी है। किसी भी क्षेत्र को अब वह यह सोचकर नहीं छोड़ देता कि उसमें औरों से मुकाबला करना उसके बूते से बाहर है। टीवी की चकाचौंध में किसी एक का चोटी पर पहुंचना हजारों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग



और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में गरीब कम पहुंच रहे हैं। शायद इसलिए कि वहां तक पहुंचने का रास्ता मंहकी स्कूलों और कोचिंग से होकर गुजरता है और सुपर थर्टी के आनंद कुमार हर जगह तो हैं नहीं। लेकिन जिन क्षेत्रों में कुदरती प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है, वहां कमजोर से कमजोर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं। संगीत और खेल इनमें प्रमुख हैं। इन पर भी हाल तक समाज के संपन्न वर्ग का ही कब्जा रहा है लेकिन जब अवसरों की बहुतायत हुई और खासकर खेल में विश्व स्तर पर मुकाबला करने की ललक देश में पैदा हुई तो प्रतिभाओं को महत्व मिलना शुरू हो गया। अभी जोर नतीजे पर है, बैकग्राउंड पर नहीं। यही वजह है कि कुछेक खेलों में

कमजोर दायरे के लोगों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। अंडर-19 क्रिकेटर्स में गोलगप्पे बेचकर कोचिंग लेने वाले यशस्वी जायसवाल की चर्चा महान क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर के बेटे अर्जुन तेंडुलकर से ज्यादा हो रही है। महिला क्रिकेटर पूनम राउत एक ड्राइवर की बेटी हैं। एशियाई खेलों में हेप्टाथलन का स्वर्ण जीतने वाली स्वप्ना बर्मन के पिता पंचानन रिकशा चलाते थे और मां चाय बागान में मजदूरी करती थीं। यूथ ओलिंपिक में जूडो का सिल्वर जीतने वाली थांगजाम तबाबी देवी के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और मां मछली बेचती हैं। जरूरत हर क्षेत्र में, हर स्तर पर चयन प्रक्रिया को समतापूर्ण बनाने की है। न जाने कितनी प्रतिभाएं समय से पहचान लिए जाने की बाट जोह रही हैं।

बहस और विवाद

अशोक वोहरा।

जाहिर है, सोचने-विचारने वालों का कोई भी समूह बहस और विवाद से बचकर यहां एक कदम भी नहीं चल सकता। उन

धर्म-दर्शन



बुजुर्ग सज्जन की सलाह इसी संदर्भ में सामने आई थी और वैचारिकता बनाए रखते हुए आपसी रिश्तों को कड़वाहट से दूर रखने के लक्ष्य से निर्देशित थी। पर जरा अलग संदर्भ में देखें तो देश की राजनीति के अलग-अलग हिस्सों ने इस सलाह पर बहुत बारीकी से अमल किया है, जिसका नतीजा आम जनता के संबंधित हिस्सों की विचारहीनता के रूप में सामने आया है। कभी दलित, कभी ओबीसी, कभी मुस्लिम— जिस समूह को इस राजनीति ने निशाने पर लिया उसका दिल जीत लिया और ऐसा जीता कि वह जनसमूह उसके सारे धतकरमों का बचाव करने में लग गया। उसे अपने हितों का भी होश नहीं रहा।

संपादकीय

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करेगी और इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के जरिए इसमें अपने स्टैक का एक हिस्सा बेचेगी। इस प्रस्ताव को सही ठहराने के लिए उन्होंने तर्क दिया है कि 'किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने से उसमें अनुशासन आता है। इससे वित्तीय बाजार को कंपनी में दखल देने का अवसर मिलता है और इसका मूल्य उन्मुक्त होता है। इस क्रम में खुदरा निवेशक भी कंपनी में भागीदारी कर सकते हैं।' इस घोषणा से मीडिया में एलआईसी को लेकर एक बहस छिड़ गई है। कुछ वित्तीय विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) में सूचीबद्ध होने से पॉलिसीधारकों को बड़ा फायदा होगा। इससे लोग एलआईसी की कार्यप्रणाली पर नजर रख पाएंगे और उसकी कॉरपोरेट गवर्नेंस सुदृढ़ होगी। आइए देखें कि एलआईसी की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है और कॉरपोरेट मीडिया उसे बदनाम करके किन स्वार्थी तत्वों का हित साध रहा है? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1956 में एलआईसी ने मात्र 5 करोड़ रुपये की धनराशि से अपना काम शुरू किया था। आज एलआईसी की विराट परिसंपत्ति का मूल्य 31 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। पिछले दो दशकों से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रवेश किया और एलआईसी को टक्कर देने की कोशिश की। इस जर्बदस्त प्रतियोगिता के बाद भी बाजार में एलआईसी का हिस्सा 73 प्रतिशत से अधिक है। यही कारण है कि 2018-19 के लिए भारत सरकार को उसकी मात्र 100 करोड़ की हिस्सा-पूँजी के बदले एलआईसी ने 2611 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है।

लेकिन किसी को इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन मुद्दों पर बात करने की हिम्मत जुटाने के लिए आपको कुछ बुद्धिजीवियों के बुरे-बुरे तंजों को भी झेलना पड़ेगा।

दिल्ली में दंगाइयों का तांडव

विश्व गौरव ।

दिल्ली... भारत की राजधानी... इसे देश का दिल भी कहते हैं...यह एक केन्द्र शासित प्रदेश है और दिल्ली पुलिस को लेकर लंबे समय तक केन्द्र और राज्य सरकार में विवाद रहा है। खैर, मुद्दा विवाद का है ही नहीं... मुद्दा है हत्या का। मुद्दा है देश के दिल की धड़कने रोकने का। मुद्दा है देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों के खिलाफ चुप्पी का। मुद्दा है उस 56 इंची छाती वाले वादे का जिसके भरोसे हमने एक राष्ट्रवादी पार्टी को देश की सत्ता सौंपी है। मुद्दा है देश को असल मुद्दों से भटकाने का। मुद्दा है उस फर्जी सेक्युलरिज्म का जिसका लेकर महीनों से कुछ नेता दंगाइयों का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। मुद्दा है उस टूटते सपने का जो भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के उद्देश्य से दशकों से देखा जा रहा था। लेकिन किसी को इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन मुद्दों पर बात करने की हिम्मत जुटाने के लिए आपको कुछ बुद्धिजीवियों के बुरे-बुरे तंजों को भी झेलना पड़ेगा।

दिल्ली में रास्ते बंद हैं, अलीगढ़ में आम लोगों को पीटा जा रहा है, देश में कई 'शाहीन बाग' बनाने की धमकियां जी जा रही हैं, देश के एक हिस्से को देश से अलग करने की बातों की जा रही हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। देश के



प्रधानमंत्री, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस काम करती है ऐसे गृहमंत्री, रक्षामंत्री समेत पूरे देश का 'मत' जिस दिल्ली में बैठता है, वहां पर महीनों से एक आधारहीन विषय को लेकर देशविरोधी बयान, पत्थरबाजी, आगजनी और न जाने क्या-क्या हो रहा है। देश के रक्षामंत्री एवं पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सड़कों पर आगजनी होती है, आम लोग घायल होते हैं लेकिन दंगाइयों पर कार्रवाई की बात आते ही मानवाधिकार कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं। हमने देश को क्या बना दिया है? कहां गई शौर्य की वे बातें, जिनके कारण हमें भरोसा हुआ था कि देश अब सुरक्षित हाथों में रहेगा।

आप सोचकर देखिए, देश के सैकड़ों स्थानों पर जो लोग आग लगा रहे हैं, वे कौन हैं? इसी देश के हैं ना? हम उनके साथ खेलते थे, खाना खाते

थे, उनके गले लगते थे लेकिन अचानक क्यों ये लोग सड़क पर उतर आए? क्यों ये अपने ही देश की संपत्ति को आग लगाने लगे? क्यों ये अपने ही वर्दी वाले भाई के सीने पर पिस्टल लगा देते हैं? क्या इन्हें डर नहीं लगता? क्या इन्हें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी अहसास नहीं है? जी नहीं! इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि इनके रहनुमा इन्हें सिर्फ झूठ सिखा रहे हैं और हमारे जिम्मेदार नेता उन कथित रहनुमाओं के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि इससे उनका 'सेक्युलरिज्म' खतरे में पड़ जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सच क्या है, उसे समझाने की सरकार और सत्ताधारी पार्टी ने बहुत कोशिश की लेकिन जाहिलियत के चरम तक पहुंचे लोग उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या विकल्प बचता है? सिर्फ तीन ही विकल्प हैं। या तो उस वजह को ही खत्म कर दीजिए, जिसकी वजह से बवाल हो रहा है, यानी सीएए को वापस ले लीजिए। या फिर बवाल कर रहे लोगों पर जाति-धर्म से ऊपर उठकर कड़ी कार्रवाई करिए। या फिर जलने दीजिए देश। सरकार! कुछ भी करिए, लेकिन एक बात याद रखिए। आपकी चुप्पी न सिर्फ दो समुदायों में विभेद बढ़ा रही है, बल्कि देश की आत्मा के साथ खिड़वाड़ भी कर रही है। और अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि देश समय के साथ सबकुछ भूल जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं।

सूटोकु नववात-5258				* * * * *			
9			6				
4	7			8	3		9
		8	7	3		1	2
		8	9		5	1	
							7
5	1		8	7			4
							9
		2	4		6	5	7
		7	1	3			
							5
							8
							4

अपना ब्लॉग जल्द जारी हों आंकड़े

मोहन।

कुछ हद तक तो कटौती समझ में आ सकती है पर जब अति महत्वपूर्ण स्कीमों में बहुत बड़ी कटौतियां की जाएं तो इससे बजट का महत्व कम होता है और सरकारी खर्च में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठता है। इसलिए अगले साल के आवंटनों पर ध्यान रखने के साथ ही पिछले साल के वास्तविक खर्च पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सरकारी खर्च की पारदर्शिता बढ़ाने और उस पर सार्थक बहस के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार यह हो सकता है कि पूरे वित्तीय वर्ष के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के आंकड़े जैसे ही प्राप्त हों, वैसे ही उन्हें अधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा जारी कर दिया जाए। इस सुधार से वास्तविक खर्च की सही स्थिति जल्दी सामने आ जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है।

